

उत्तर प्रदेश: सेमीकंडक्टर वनिरिमाण इकाइयों के लिये अनुकूल

चर्चा में क्यों?

एक बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य की प्रस्तावित **सेमीकंडक्टर नीति 2024** पर आधारित प्रस्तुतीकरण की समीक्षा की और अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किये।

मुख्य बटु:

- मुख्यमंत्री ने कहा कि **सेमीकंडक्टर वनिरिमाण उद्योगों में उन्नत के साथ-साथ उच्च दक्षता वाले उपकरणों जैसे स्मार्टफोन, कंप्यूटर और चकितिसा संबंधित उपकरणों में के लिये महत्त्वपूर्ण है।**
 - यह **आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स और क्वांटम कंप्यूटिंग में नवाचार** को भी बढ़ावा देता है।
- यह **राज्य की आर्थिक वृद्धि** और नवाचार में योगदान देगा तथा रणनीतिक रूप से महत्त्वपूर्ण क्षेत्रों में आत्मनिर्भरता को बढ़ाते हुए पर्याप्त रोजगार के अवसर भी उत्पन्न करेगा।
- युवाओं को सेमीकंडक्टर निर्माण में प्रशिक्षण प्रदान करने के लिये** मुख्यमंत्री ने राज्य के दो IIT सहित तकनीकी संस्थानों में ऐसे पाठ्यक्रमों को शामिल करने का प्रस्ताव रखा।
 - सेमीकंडक्टर उद्योगों में CM इंटरनशिप कार्यक्रम के तहत युवाओं के लिये दो वर्ष के प्रशिक्षण की व्यवस्था** की जानी चाहिये।
- सेमीकंडक्टर चपि क्षेत्र** ने पछिले दो वर्षों में **500 बलियिन अमेरिकी डॉलर से अधिक नविश करने की योजना** की घोषणा की है।
 - सेमीकंडक्टर क्षेत्र में नविश आकर्षित करने के लिये, **भारत सरकार ने 10 बलियिन अमेरिकी डॉलर का प्रोत्साहन परविय प्रदान करने का नरिणय लिया है।**
- सीएम का सुझाव है** कि नीति में वैश्विक सेमीकंडक्टर नविशकों को आकर्षित करने के लिये वित्तीय और गैर-वित्तीय प्रोत्साहन के वतारण के प्रावधान शामिल होने चाहिये।
 - ऐसा करने वाला **उत्तर प्रदेश देश का चौथा राज्य** होगा।
- नई नीति में भारत सरकार द्वारा अनुमोदित पूंजी के अलावा **अतिरिक्त पूंजी नविश** भी शामिल होना चाहिये।
 - भूमि की खरीद/पट्टे पर स्टाम्प शुल्क में छूट** का भी प्रावधान होना चाहिये।
- नीति में वदियुत शुल्क में छूट, ड्यूल पावर ग्रडि नेटवर्क ट्रांसमिशन एवं वहीलिंग शुल्क, कौशल वकिकास एवं प्रशिक्षण, पेटेंट, जल आपूर्ति, पावर बैंकगि, अनुसंधान और वकिकास सहायता हेतु प्रावधान किये जाने चाहिये।**